Popular Front of India

+91 11 46526919
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
22 मार्च 2021

पॉपुलर फ्रंट के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन; न्यायपालिका से देश को धार्मिक फासीवाद से संवैधानिक मूल्यों की तरफ वापस लाने में अपना रोल निभाने की अपील

केरल के मलप्पुरम में आयोजित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक मौजूदा राष्ट्रीय परिस्थितियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई। बैठक में पारित एक प्रस्ताव में न्यायपालिका से यह अपील की गई कि वह आज़ादी व न्याय के रक्षक की हैसियत से अपना रोल निभाते हुए देश के तानाशाही की तरफ बढ़ते रूझानों पर रोक लगाए। पॉपुलर फ्रंट ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करते हुए मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं में खलल डालने और उनके धार्मिक स्थलों पर क़ब्ज़ा करने की संघ परिवार की कोशिशों पर पूर्ण विराम लगाए।

एक तरफ बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की न्यायपालिका पर एक दाग बना हुआ है, और दूसरी तरफ लोगों का एक वर्ग यह समझता और उम्मीद करता है कि बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के दावे के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देशभर में शांति व सौहार्द का कारण बनेगा। लेकिन हाल के घटनाक्रम यह बताते हैं कि शांति के नाम पर न्याय का गला घोंटना शांति लाने में कुछ काम नहीं आया है। जो संघ परिवार दशकों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता आया है, जिसके नतीजे में 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और मुस्लिम विरोधी हिंसा की घटनाएं घटीं, उसने आज भी अपने इरादों और काम करने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके विपरीत उसने अयोध्या आंदोलन की तरह अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों के खिलाफ नए आंदोलन और अभियान शुरू कर दिए हैं। मथुरा शाही ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने की याचिकाएं और धार्मिक स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई पीआईएल आरएसएस की रणनीति के नए दौर का हिस्सा हैं। पॉपुलर फ्रंट ने न्यायपालिका से इन याचिकाओं के पीछे के हिंसक व विभाजनकारी एजेंडे को देखते हुए मज़बूत स्टैंड लेने की अपील की है, ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर नए हमलों को रोका जा सके।

राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पारित एक अन्य प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट ने उन सभी राज्यों की जनता से, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की हार को सुनिश्चित बनाने की अपील की है। आने वाले सप्ताहों में, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जनता महंगाई, बेरोज़गारी और गरीबी से जूझ रही है, ऐसे हालात में आरएसएस की मातहत बीजेपी सरकार लगातार काले कानूनों और तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों के अपनी शिकायतें जताने के लोकतांत्रिक दायरे को तंग कर रही है। लोगों के शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक आंदोलनों को ताकत और बर्बरता के द्वारा कुचला जा रहा है। व्यक्तियों और संगठनों

को केंद्रीय सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बात करने की वजह से अपराध व आर्थिक जांच एजेंसियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अपने 6 वर्षीय शासनकाल में, मोदी सरकार ने वह सब कुछ तबाह करके रख दिया है जो भारत ने पिछले 7 दशकों में प्राप्त किया था। पूरा विश्व अब इस हकीकत को स्वीकार कर रहा है। हाल के दिनों में दो बड़ी वैश्विक संस्थाओं ने अपनी रैंकिंग में भारत का स्थान बहुत नीचे पहुंचा दिया है, इस हकीकत से जनता की आंखें खुलनी चाहिएं। अमेरिकी रिसर्च संस्था 'फ्रीडम हाउस' ने भारत की रैंकिंग ''आंशिक आज़ाद'' देश के तौर पर की है, तो स्वीडिश संस्था 'वी–डेम' ने अपनी रिपोर्ट में भारत को ''चुनावी तानाशाही'' बताया है। बैठक में उपरोक्त राज्यों की जनता से अपील की गई है कि वे बीजेपी की हार को सुनिश्चित बनाते हुए अपने वोट का प्रयोग करें और भागवत–मोदी–शाह सरकार की जन–विरोधी, गरीब–विरोधी व विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ उन्हें खुली चेतावनी दें।

बैठक ने सभी नागरिकों, समूहों, संगठनों, संस्थाओं और पार्टियों को याद दिलाते हुए कहा कि हमारा सेक्युलर लोकतांत्रिक गणतंत्र आरएसएस की विचारधारा और रणनीति के चंगुल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आरएसएस के इशारों पर चलने वाली केंद्रीय व राज्य सरकारों के द्वारा सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग भारत को अराजकता और अफरा–तफरी की तरफ ले जा रहा है।

हिंदुत्व ताकतों ने सरकार की मदद से नफरत, शक, विभाजन, असुरक्षा और हिंसा के जिस माहौल को बढ़ावा दिया है, उसके शिकार केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हैं। इतिहास साक्षी है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों और ''आंतरिक दुश्मन'' बताए जाने वाले अन्य वर्गों से युद्ध पर तुले धार्मिक फासीवाद से आखिर में बहुसंख्यक वर्गों का जीवन भी सुरक्षित नहीं बचेगा, जिन्हें सुरक्षा देने के नाम पर गुमराह, भड़काया और उनका सैन्यीकरण किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में विभिन्न हिंदू धार्मिक वर्गों, समुदायों, संतो और नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे आगे बढ़ कर भारत और उसकी जनता को इस नाजुक व ऐतिहासिक मोड़ पर आरएसएस के विनाशकारी प्रभाव से बचाएं।

यह दो दिवसीय बैठक चेयरमैन ओ एम ए सलाम के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुई। महासचिव अनीस अहमद ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिखाया गया कि महामारी की पाबंदियों और दमनकारी तरीकों से सामान्य गतिविधियों को प्रभावित करने की सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद देश भर में संगठन में ज़बरदस्त विकास किया है। बैठक में विभिन्न राज्यों के अंदर कोविड–19 राहत सेवाओं विशेषकर कोविड से मरने वाले सैकड़ों लोगों के अंतिम संस्कार में संगठन के कार्यकर्ताओं और यूनिटों के कामों की सराहना की गई। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया।

अनीस अहमद
महासचिव,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली